जनसत्ता

निवेश के रास्ते

भारत ने सऊदी अरब की कंपनियों को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करने और नए उद्योगों (स्टार्टअप) में पूंजी लगाने का जो न्योता दिया है, वह निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों का संकेत है। अगर इस तरह की पहल कामयाब होती है और सऊदी अरब की कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो भारत के ऊर्जा क्षेत्र का विकास होगा और अर्थव्यवस्था भी जोर पकड़ेगी। इन दिनों सऊदी अरब की राजधानी रियाद में चल रहे निवेशक सम्मेलन में दुनियाभर के निवेशक पहुंचे हैं। भारत में पिछले कई महीनों से अर्थव्यवस्था में मंदी का जो माहौल बना हुआ है, उसका एक बड़ा कारण निवेश नहीं आना भी रहा है। ऐसे में बाहर से निवेश का आना अर्थव्यवस्था की बड़ी जरूरत भी है। सऊदी अरब ने भारत में सौ अरब डॉलर के निवेश के संकेत भी दिए हैं। इसके अलावा भारतीय कंपनियां भी सऊदी अरब की कई बड़ी परियोजनाओं में अपनी भागीदारी बढ़ा रही हैं। दोनों देशों के बीच सालाना कारोबार साढ़े सत्ताईस अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गया है। इस लिहाज से भी भारत के लिए सऊदी अरब एक बड़े व्यापारिक साझीदार के रूप में सामने आया है।

अब तक माना जाता था कि सऊदी अरब के संबंध भारत के मुकाबले पाकिस्तान के साथ ज्यादा मजबूत हैं और वक्त पड़ने पर वह पाकिस्तान का साथ देता रहा है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआइसी में भी सऊदी अरब का दबदबा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हालात बदले हैं और सऊदी अरब ने दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का लोहा माना है। भारत ने 2008 में 'लुक ईस्ट' की जो नीति शुरू की थी, उसका असर अब साफ दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्तों के साथ-साथ कूटनीतिक रिश्तों का भी दौर शुरू हुआ। मुसलिम देशों के बीच भारत की पैठ बनाने में सऊदी अरब की बड़ी भूमिका रही। सऊदी अरब इस बात को अच्छी तरह जानता-समझता है कि भारत लंबे समय से आतंकवाद की मार झेल रहा है और इसमें उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान की क्या भूमिका है। इसलिए भारत और सऊदी अरब दोनों ने ही समय-समय पर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है और इस समस्या से मिल कर लड़ने और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए, जिनमें आतंक के खिलाफ सूचनाओं के आदान-प्रदान जैसे समझौते भी शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब ने कभी भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में सऊदी अरब और भारत के बीच अगर कारोबारी रिश्तों को नया आयाम और विस्तार मिलता है तो यह दोनों देशों के लिए स्वर्णिम मौका होगा।

अरब जगत में सऊदी अरब ऐसा देश है जहां लाखों भारतीय कामगार हैं और ये न सिर्फ सऊदी अरब के विकास की रीढ़ साबित हुए हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान दे रहे हैं। इनसे भारत को ग्यारह अरब डॉलर सालाना से ज्यादा की विदेशी मुद्रा मिलती है। भारत सऊदी अरब से बाईस अरब डॉलर सालाना के पेट्रोलियम उत्पाद खरीदता है। भारत के लिए सऊदी अरब इसलिए भी अहम है कि इराक के बाद सबसे ज्यादा कच्चा तेल उसी से मिलता है। ऐसे में सऊदी कंपनियों के लिए भारत निवेश का बड़ा ठिकाना बन सकता है। नए उद्योगों को भी निवेशकों की दरकार है। हालांकि निवेश करने वाली कंपनियां संबंधित देश से अपने लिए अच्छे कारोबारी माहौल और कर रियायतों की उम्मीदें करती हैं। पिछले कुछ समय में कारोबारी सुगमता के मामले में भी भारत की वैश्विक रैंकिंग सुधरी है। इससे भी निवेशकों में भारत के प्रति भरोसा पैदा होगा।

लापरवाही का प्रदूषण

जिस समय समूचे देश और खासकर राजधानी दिल्ली में जहरीली होती हवा एक गहरी चिंता का विषय है, उसमें अगर कचरे के पहाड़ से फैलते प्रदूषण की खबरें आती हैं तो स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि क्या सरकार इस समस्या से निपटने के प्रति ईमानदार है! गौरतलब है कि पिछले काफी दिनों से दिल्ली के भलस्वा डेरी इलाके में कचरे के पहाड़ से फैलते प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जा रही है। फिर ओखला और गाजीपुर में भी हालत इससे अलग नहीं है। लेकिन इस ओर सरकार को ध्यान देना शायद जरूरी नहीं लग रहा है। नतीजतन, पहले ही धुएं और धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली में दम घुटने की स्थिति पैदा हो रही है। भलस्वा डेरी में मौजूद कचरे के पहाड़ से उपजी समस्या कोई नई नहीं है। हालत यह है कि इसमें कई बार लगी आग की वजह से आसपास के इलाकों में लोगों का सहजता से सांस लेना तक दूभर होता रहा है। जब भी समस्या गहरा कर किसी तरह सुर्खियों में आ जाती है तब सरकार की ओर से इस तरह के आश्वासन जारी किए जाते हैं कि जल्दी ही कचरे के ढेर से निपटान के इंतजाम किए जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर सभी आश्वासनों को शायद भुला दिया जाता है।

सरकार और संबंधित महकमों की ऐसी ही लापरवाही और अनदेखी का नतीजा है कि कचरे के ये पहाड़ आज राजधानी की बड़ी समस्या बन चुके हैं। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भलस्वा डेरी के पास करीब सत्तर एकड़ में कचरा और मलबा डालने के जारी क्रम की वजह से इसकी ऊंचाई आज सतह से बासठ मीटर ऊपर हो चुकी है। करीब अस्सी लाख टन कूड़े का बोझ बन चुके इस पहाड़ पर सड़ते हुए कचरे से जिस तरह का प्रदूषण फैल रहा है, उसके प्रति आंखें मूंद लेने के रवैये ने आज हालत यह कर दी है कि उस समूचे इलाके में स्थित कई कॉलोनियों में रहने वाले लोगों में सांस फूलने, टीबी, एलर्जी, दूषित पानी की वजह से पेट के रोगों सहित कई गंभीर बीमारियां जड़ पकड़ रही हैं। सवाल है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए ऑड-इवन सहित दूसरे तमाम इंतजामों की घोषणा करती सरकार की नजर में क्या कचरे के पहाड़ से फैलते प्रदूषण से उपजी समस्या की कोई जगह है? मुश्किल यह है कि कई बार अदालती निर्देशों के बावजूद इसके हल के लिए कोई ठोस पहलकदमी अब तक नहीं हो सकी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल दिल्ली में ठोस कचरे को बेहद गंभीर समस्या बताया था और यहां के उपराज्यपाल को इससे निपटने के लिए विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी के सदस्यों और आवासीय संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति बनाने के लिए कहा था। इसके अलावा, करीब एक सौ अस्सी करोड़ रुपए खर्च कर भलस्वा कचरा पट्टी को दक्षिण कोरिया के सियोल स्थित नजीदों कचरा पट्टी की तर्ज पर संवारने की योजना है। लेकिन आज दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर हालत में पहुंच जाने के बाद यह कहना मुश्किल है कि अदालत के निर्देशों सहित बाकी योजनाओं पर कितना अमल हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि उचित निपटान की व्यवस्था हो तो पचास फीसद कचरे को कम्पोस्ट खाद में बदला जा सकता है। इसके अलावा, तीस फीसद कचरे का पुनर्चक्रण भी किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि कचरा निपटान केंद्रों तक केवल बीस फीसद कचरा पहुंचेगा। सवाल है कि राजधानी में भलस्वा, ओखला और गाजीपुर में कचरे के पहाड़ की ऊंचाई के लगातार बढ़ने के क्रम में इस तरह के उपायों पर कितना गौर किया गया?

कल्पमेधा

अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा।
-एपीजे अब्दुल कलाम

आर्थिक भेदभाव से जूझता समाज

ज्योति सिडाना

यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की छवि के बावजूद निर्धन जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस कारण अगर अनेक परिवार जीविका, स्वास्थ्य, भुखमरी, कुपोषण से संघर्ष करने में असफल हो रहे हैं तो उनके सामने सामूहिक आत्महत्या, हत्या अथवा अन्य अपराध जैसे विकल्प उभर कर आ सकते हैं।

मनुष्य को जीवन संचालन के लिए कई प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन संसाधनों की अनुपलब्धता या कमी निर्धनता को व्यक्त करती है। कुछ समाज विज्ञानी केवल भौतिक संसाधनों की कमी को निर्धनता का आधार मानते हैं, जबकि कुछ शैक्षणिक अवसरों की अनुपलब्धता, कार्य स्थितियों में कमी, शक्तिहीनता और सामाजिक बहिष्कार को भी निर्धनता के साथ जोड़ कर देखते हैं। ये वे पक्ष हैं जो समाज की इकाइयों को अनेक गतिविधियों में सहभागिता न करने के लिए बाध्य करते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के उपरांत तो निर्धनता की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। ब्रिटिश समाज विज्ञानी राल्फ मिलिबेंड तर्क देते हैं कि निर्धनता को असमानता की संरचना के साथ देखे जाने की जरूरत है। जैसे-जैसे निर्धनता का विस्तार होता है, समाज में असमानता और अधिक जटिल होती जाती है।

हाल में भुखमरी का सामना कर रहे एक सौ सत्रह देशों के संदर्भ में वैश्विक भुखमरी सूचकांक की रिपोर्ट आई है। इस सूची में भारत का स्थान एक सौ दो वां है, जबकि पाकिस्तान चौरानबेवें, बांग्लादेश अट्ठासीवें, नेपाल तिहत्तरवें और श्रीलंका छियासठवें स्थान पर है। वर्ष 2017 में भारत एक सौ उन्नीस देशों की सूची में सौवें स्थान पर था और 2018 में एक सौ तीनवें स्थान पर। यदि 2014 के आंकड़ों से तुलना करें तो तब भारत पचपनवें स्थान पर था। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि देश में भुखमरी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, अपितु भारत अपने पड़ोसी देशों से भी खराब स्थिति में आ गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के पहले राष्ट्रीय पोषण सर्वे के अनुसार देश में दस से उन्नीस साल आयु वर्ग के चार बच्चों में से एक बच्चा कुपोषित है।

महात्मा गांधी ने राष्ट्र के विकास में प्रत्येक निर्धन इकाई की सहभागिता को पर्याप्त महत्त्व दिया था, ताकि वह निर्धनता, बेकारी और भुखमरी से मुकाबला करने के तरीके खुद खोज सके। परंतु वर्तमान उपभोक्तावादी और नव-उदारवादी समाज में धनाढ्य और निर्धन वर्ग में बढ़ती खाई ने अनेक समस्यामूलक स्थितियों को उत्पन्न कर दिया है, जिसने निम्न एवं मध्य वर्ग के समक्ष अस्तित्व की निरंतरता को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ही है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य की छवि के बावजूद निर्धन जनसंख्या को न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इस कारण अगर अनेक परिवार जीविका, स्वास्थ्य, भुखमरी, कुपोषण से संघर्ष करने में असफल हो रहे हैं तो उनके सामने सामूहिक आत्महत्या, हत्या अथवा अन्य अपराध जैसे विकल्प उभर कर आ सकते हैं।

गरीबी के पैमाने का निर्धारण करने के लिए रंगराजन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ग्रामीण और शहरी निर्धनता के लिए क्रमशः बत्तीस और सैंतालीस रुपए प्रतिदिन व्यय का मानक तय किया था। जबकि अर्जुन सेनगुप्ता कमेटी ने यह राशि बीस रुपए प्रतिदिन तय की थी। ये रिपोर्टें चाहे कितनी ही विवादास्पद हों, पर इस तथ्य को स्थापित करती हैं कि देश की जनसंख्या का लगभग पैंतीस फीसद भाग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विस्तार ले रही निर्धनता इस समय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सवाल है। इस पैंतीस फीसद आबादी और फिर निर्धनता की सीमा के इर्दगिर्द वाली आबादी से संबद्ध युवा लगभग सभी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। परिणामस्वरूप विकास प्रक्रिया में इस आबादी की सहभागिता का सवाल हाशिये पर चला जाता है। यह आर्थिक विषमता अनेक बुनियादी सवालों को जन्म देती है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कुपोषण, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की लंबाई औसत से कम होना, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन औसत से कम होना और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु होना जैसे चार प्रमुख संकेतकों को आधार बनाया गया है। इन चार संकेतकों में से बच्चों का कम वजन होना भारत का सूची में निम्न स्थान पर आने का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन औसत से बहुत कम निकला है, जो चिंता का विषय है क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं जो स्वयं स्वस्थ नहीं रहेंगे एक स्वस्थ देश का निर्माण कैसे कर पाएंगे?

विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम) द्वारा हाल में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को इस साल एक सौ इकतालीस देशों की सूची में अड़सठवें पायदान पर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अपनाने में सुस्त रहने, स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में खराब स्थिति होने और स्वस्थ जीवन की खराब संभावनाओं के कारण पिछड़ गया। यहां तक कि स्वस्थ जीवन की संभावना में तो भारत का स्थान एक सौ नौ वां रहा, लैंगिक असमानता में भारत एक सौ अट्ठाईस वें स्थान पर रहा और सबसे बड़ी बात तो ये कि विश्व शांति सूचकांक (ग्लोबल पीस इंडेक्स) में पिछले वर्ष की तुलना में भारत पांच स्थान नीचे गिर कर एक सौ इकतालीसवें स्थान पर आ गया। आज आवश्यकता है इन सब आंकड़ों को ध्यान में रख कर चिंतन करने की, ताकि समय रहते विकास के समावेशी प्रारूप को मूर्त रूप दिया जा सके।

इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा सेवाएं भारत वर्ष में कारपोरेट बाजार का हिस्सा बनती जा रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण ने डॉक्टर-रोगी के मध्य सबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में जांच उपकरण खराब पड़े होने या आधुनिक उपकरण न होने के कारण रोगी को संबंधित जांच प्राइवेट केंद्रों पर करवाने के लिए बाध्य होना पड़ता है और निर्धनता की वजह से वे स्वास्थ्य लाभ से वंचित रह जाते हैं। अधिकांश निर्धन महिलाओं के प्रसव तो अस्पतालों के बाहर या बीच सड़क पर ही हो जाते हैं। ऐसे में मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर के औसत से अधिक होने की संभावना से कैसे इंकार किया जा सकता है?

इसे विरोधाभास ही कहा जाएगा कि एक तरफ आबादी का एक हिस्सा अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए वैवाहिक समारोहों एवं अन्य समारोहों में खाने की बर्बादी करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत कुपोषण, एनीमिया, भुखमरी के कारण दुनिया के पैमाने पर शर्मनाक स्थिति में है। यह विकास की कैसी तस्वीर है जो एक तरफ यह स्थापित करती है कि भारत तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में उच्च स्थान पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, खुशहाली, बेरोजगारी और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से निम्न स्थान पर खड़ा नजर आता है। एक तरफ ऐसा वर्ग है जो धनाढ्यों के क्रम में सर्वोच्च स्थान पाने, सर्वाधिक शक्तिशाली बनने और लोकप्रिय होने जैसी आकांक्षाओं से घिरा है और दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जिसके सामने अस्तित्व बचाने का संकट गहराता जा रहा है।

कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो फिर अगर किसी देश के अधिकांश नागरिकों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ही संकट का सामना कर रहा हो या चुनौती प्राप्त कर रहा हो तो उस देश का विकास संदेहास्पद हो जाता है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, अपितु सवाल यह है कि यह किस तरह का विकास है जो एक ही देश में एक ही समय में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तस्वीरों को एक साथ दिखा रहा है। जबकि विकास का वास्तविक अर्थ संसाधनों का तर्कसंगत विभाजन और विस्तार है, ताकि नागरिक अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

जीवन की खातिर

हेमंत कुमार पारीक

दिल्ली में मेट्रो चली तो उसका जोरशोर से स्वागत हुआ था। इसलिए भी कि दिल्ली की जनसंख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और नतीजतन, आवागमन के साधन अपर्याप्त हो गए थे। शहर की जरूरत के मुताबिक सार्वजनिक परिवहन की काफी कमी थी। दिल्ली परिवहन निगम की बसें जनसंख्या का बोझ नहीं उठा पा रही थीं। आज देश के दूसरे शहरों और यहां तक कि राज्यों की राजधानियों का भी यही हाल है। रोजगार की तलाश में लोग हर रोज गांवों से पलायन कर शहर की तरफ आ रहे हैं। जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से आवागमन के नए-नए साधनों के विकास पर सरकार का ध्यान जा रहा है। लेकिन इसी क्रम में हरे-भरे पेड़ों को बेदर्दी से काटा जा रहा है। जनहित की आड़ में घने जंगलों की बलि दी जा रही है और जंगल मैदानों में तब्दील हो रहे हैं।

मुंबई की लोकल ट्रेन कई सालों से आबादी के इस बोझ से जूझ रही है। इसी प्रकार, कोलकाता की ट्रामें भी सालों से अपना कार्य सुचारु रूप से कर रही हैं। लेकिन जब दिल्ली की मेट्रो राजनीति के गलियारों में 'दूध देती गाय' नजर आई, तभी से बिना सोचे समझे, पर्यावरण की हानि का जायजा लिए बगैर मेट्रो प्रोजेक्ट को देश के दूसरे राज्यों, शहरों और राज्यों की राजधानियों में हरी झंडी दिखाई जाने लगी है। इसी के चलते जयपुर और लखनऊ में मेट्रो का पदार्पण हुआ। मुंबई में मेट्रो परियोजना काम कर रही है। इसी परियोजना के चलते आरे कॉलोनी सुर्खियों में आई। वहां करीब दो-तीन हजार पेड़ों की बलि दी जाने वाली थी। लेकिन वहां की पर्यावरण प्रेमी जागरूक जनता को समझ में आया तो चारों तरफ से आवाज उठने लगी। कई समाजसेवी संस्थाएं और फिल्मी हस्तियां आगे आईं और विरोध में उठ खड़ी हुईं। एक जागरूक समाज अपने वर्तमान के साथ-साथ अपने भविष्य के लिए भी जतन करता है।

दुनिया मेरे आगे

हाल ही में स्वीडन की एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग की ऐसी ही आवाज दुनिया की संसद में सुनाई दी है। उसने दुनिया भर के बड़े-बड़े राजनेताओं को चेतावनी दे डाली। पर्यावरण प्रेमी एक लड़की की आवाज पूरी दुनिया ने सुनी।

कुछ ही दिनों पहले पर्यावरण को प्रभावित करने वाली दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। पहली, अमेजन के जंगलों में लगी आग और दूसरी अंटार्कटिका के पिघलते हिमखंड। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया का ध्यान खींचा है। अमेजन के जंगलों को 'कार्बन सिंक' कहा जाता है। ये जंगल बहुत घने हैं। विभिन्न प्रकार के जीव-जंतु यहां पाए जाते हैं और दुनिया भर की उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को ये वन सोख लेते हैं। यानी एक तरह से ये ओजोन परत को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाने का महत्त्वपूर्ण काम करते हैं। इस कारण दुनियाभर के देशों के राजनीतिकों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। चूंकि अमेजन के जंगलों में लगी आग समूची दुनिया पर असर डालने वाली घटना है, इसीलिए सभी ने मिल कर आग पर काबू पाने के लिए अपने-अपने प्रस्ताव रखे। यह चिंता सकारात्मक है और पृथ्वी को बचाने के लिहाज से जरूरी है।

पर्यावरण से जुड़ी दूसरी घटना है दक्षिणी ध्रुव के बर्फीले अंटार्कटिका में एक विशाल हिमखंड का टूट जाना। पिछले पचास वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि वैज्ञानिक 'लूज-टूथ' नाम के हिमखंड के पिघलने की चेतावनी पिछले कई सालों से दे रहे थे, पर यह दूसरा हिस्सा था, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह छोटा-मोटा हिमखंड नहीं था, बल्कि इतना विशाल था कि इसमें पूरी दिल्ली समा जाती। यही नहीं, इसके आकार के लिहाज से देखें तो इसमें दिल्ली से सटे गाजियाबाद और मथुरा भी निपट जाते। ये चेतावनियां हैं प्रकृति की, दुनिया में बढ़ते तापमान के लिए। अगर हम अब भी नहीं संभले और इसी गति से हिमखंड पिघलते रहे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिर क्या होगा? इसका सीधा असर समुद्र के जलस्तर पर पड़ेगा। जलस्तर बढ़ेगा और फिर बड़े-बड़े भूखंड देखते ही देखते समुद्र में विलीन हो जाएंगे।

इस वर्ष इतनी बारिश हमारे देश में हुई कि उसने पिछले सौ वर्षों में हुई बारिश के रिकार्ड तोड़ दिए। मानसून आया, पर जाने का नाम नहीं ले रहा था, जबकि इसकी अवधि कब की समाप्त हो चुकी थी। बाढ़ ने उग्र रूप दिखाया, नतीजतन पटना जैसे शहर जलमग्न रहे। लोग हाल-बेहाल हुए। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। घर और बाजारों में नदी-नाले बह निकले। सड़कों पर नावें चलने लगीं। ऐसे में स्वीडन की उस लड़की ग्रेटा की चेतावनी पर ध्यान देने की जरूरत है। हर आदमी को पर्यावरण के विषय में सोचने की जरूरत है। जागरूक होने का वक्त है। जिस तरह आरे कॉलोनी के लिए आम लोगों के साथ-साथ बॉलीवुड के सितारे पर्यावरण बचाने के पक्ष में सड़कों पर उतर आए थे, हमें भी पर्यावरण के संबंध में ग्रेटा के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

गांधी का रास्ता

प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि गांधीजी के विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए सिने जगत आगे आए और उसे गांधीजी के विचारों पर आधारित फिल्में बनानी चाहिए। हमारा मानना है कि आम जनता को गांधीजी के विचारों को समझने से ज्यादा जरूरी है कि राजनीति से जुड़े लोग गांधीजी के विचारों समझें और उनका अनुसरण करें। इस संदर्भ में गांधीजी का जो विचार सबसे ज्यादा प्रासंगिक है वह है 'राजनीति का अध्यात्मीकरण'।

वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में फैली बुराइयों को समाप्त करने का सबसे प्रभावी गांधीवादी विचार है- राजनीति का अध्यात्मीकरण। वर्तमान राजनीति की बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता, अवसरवाद आदि को समाप्त करके उनके स्थान पर राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, सर्वोदय, सत्य, अहिंसा, नैतिकता, परोपकार, सादगी, समर्पण, सेवाभाव, त्याग और बलिदान जैसे मूल्यों को राजनीति में शामिल करना ही राजनीति का अध्यात्मीकरण है।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक कौटिल्य राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके देखते थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साम दाम दंड भेद किसी भी नीति का अनुसरण किया जा सकता है। अर्थात हमारा साध्य शुभ है तो साधनों की परवाह नहीं करनी चाहिए। कौटिल्य ने अपने अखंड भारत के सपने को साकार करने के लिए इसी मार्ग का अनुसरण किया। पाश्चात्य राजनीति में इन विचारों का प्रणेता मैकियावली को माना जाता है इसीलिए कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है।

लेकिन आधुनिक भारतीय चिंतक गांधीजी कौटिल्य और मैकियावली के विचारों के विपरीत विचार रखते हैं। गांधीजी का मानना था कि न केवल साध्य पवित्र होना चाहिए बल्कि साधन भी पवित्र होना चाहिए। इसीलिए गांधीजी ने स्वतंत्रता के लिए हिंसक मार्ग का समर्थन न करके सत्याग्रह, असहयोग, सविनय अवज्ञा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल कर आजादी प्राप्त करने की राह देशवासियों को दिखाई। गांधीजी के इन्हीं विचारों को राजनीति का अध्यात्मीकरण कहते हैं।

राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राज्य को केवल ईश्वर की इच्छा का क्रियान्वयन करना चाहिए अर्थात कोई भी कानून बनाते समय विधायिका को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या यह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है? यदि है, तो उसे कानून का रूप देना उचित होगा अन्यथा उसे पारित होने से विधायकों को रोकना होगा। इसी प्रकार कार्यपालिका के सदस्यों को ईश्वर के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। उनको सदैव इस बात पर विचार करते रहना होगा कि मेरी जगह यदि ईश्वर स्वयं होते तो वे क्या करते और अंतःप्रज्ञा की आवाज के अनुसार कार्य करना चाहिए क्योंकि अंतःप्रज्ञा की आवाज ईश्वर की आवाज मानी जाती है। इसी प्रकार न्यायपालिका को भी विधिक न्याय के स्थान पर सामाजिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए न्याय करना चाहिए।

● *अरविंद सिंह, नई दिल्ली*

दर्द से बेखबर

महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाले के कारण उसके ग्राहकों को न केवल भारी परेशानी उठानी पड़ रही है, बल्कि तीन ग्राहकों की सदमे के कारण मौत भी हो चुकी है। किसी भी लोकतंत्र में जनता का दर्द सरकार का दर्द होता है क्योंकि जनता के वोटों से ही सरकार बनती है। लेकिन हमारे लोकतंत्र का क्रूर मजाक है कि वोट लेने के बाद जनप्रतिनिधि जनता के दर्द को समझने के बजाय उसकी अनदेखी करते रहते हैं। उन्हें जनता के दर्द को अपना दर्द समझना होगा। जनता के हित में ऐसे सभी विधायिका को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या यह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप है? यदि है, तो उसे कानून का रूप देना उचित होगा अन्यथा उसे पारित होने से विधायकों को रोकना होगा। इसी प्रकार कार्यपालिका के सदस्यों को ईश्वर के एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। उनको सदैव इस बात पर विचार करते रहना होगा कि मेरी जगह यदि ईश्वर स्वयं होते तो वे क्या करते और अंतःप्रज्ञा की आवाज के अनुसार कार्य करना चाहिए क्योंकि अंतःप्रज्ञा की आवाज ईश्वर की आवाज मानी जाती है। इसी प्रकार न्यायपालिका को भी विधिक न्याय के स्थान पर सामाजिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए न्याय करना चाहिए।

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

उपाय करने होंगे जो उसे मौत के मुंह में न ले जाएं।

● *हेमा हरि उपाध्याय अक्षत, खाचरोद, उज्जैन*

आतंक के खिलाफ

संपादकीय 'बगदादी का अंत' (29 अक्तूबर) पढ़ा। एक बड़े आतंकवादी के मरने पर आम तौर पर पूरी दुनिया यह मन लेती है की हमें आतंक के खिलाफ जंग में एक बड़ी कामयाबी मिल गई और यह लड़ाई एक निर्णायक दौर में पहुंच गई। मगर ऐसा होता नहीं है। आइएसआइएस के सरगना अबु बकर अल-बगदादी की मौत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि जरूर है मगर बगदादी के मरने से वैश्विक आतंकवाद के काम होने की कोई संभावना नहीं है। इतिहास गवाह है कि उसामा बिन लादेन की मौत के बाद भी न आतंकवाद कम हुआ न आतंकी संगठन कमजोर पड़े। उलटे बगदादी और आइएसआइएस उसामा और अल कायदा से ज्यादा खतरनाक साबित हुए। इससे लगता है कि भविष्य का आतंकवाद और क्रूर और खतरनाक होगा क्योंकि इसका दायरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है।

ज्यादातर वैश्विक आतंकी संगठनों को अलग-अलग देशों ने अपने-अपने फायदे के लिए पाला-पोसा और इन्हें अत्याधुनिक हथियार और तकनीकें मुहैया कराईं। दरअसल, आतंकी सरगनाओं को मारने से कहीं ज्यादा जरूरी है आतंकवाद को स्थायी रूप से खत्म करना, और यह तभी होगा जब तमाम देश आतंकवादियों और उनके संगठनों को तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक मदद बंद कर देंगे।

● *बृजेश माथुर, बृज विहार, गाजियाबाद*

पराली और प्रदूषण

आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। सरकार के कई कदम उठाने के बावजूद किसानों ने पराली जलाने से कोई परहेज नहीं किया। इसका नतीजा हम वायु प्रदूषण सूचकांक में देख सकते हैं जिसमें मंडी गोबिंदगढ़, जालंधर और लुधियाना जैसे शहरों की हवा सबसे प्रदूषित पाई गई है। इस हालत के लिए जिम्मेदार सिर्फ सरकार नहीं है क्योंकि उसने तो किसानों को बेहद सख्त तरीके से समझाया पर किसान हैं कि माने नहीं। यह जानकर भी कि पराली जलाने का असर हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा, वे नहीं रुके और अपनी जिद पर अड़े रहे। अब सरकार की प्रदूषित वायु को शुद्ध करने की चिंता दीवाली के पटाखों पर रुकेगी। पर क्या सिर्फ पटाखों को रोकने या उन्हें फोड़ने का समय तय कर देने भर से वायु को साफ किया जा सकता है? 365 दिन की समस्या को सिर्फ एक दिन के प्रतिबंध से काबू नहीं किया जा सकता है इसलिए सरकार को ऐसा हल ढूंढ़ना चाहिए जो लंबे सफर का साथी हो।

● *जानवी बिट्टल, जालंधर*

epaper.jansatta.com